जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 50 संख्याः 230 प्रभात कोटा, बुधवार 4 जून, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

''नरेन्दर, सरैण्डर'' भोपाल में राहुल गांधी ने प्र.मंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष किया

राहुल गांधी के अनुसार, ट्रम्प के इस मैसेज के कारण ही, जीती हुई स्थिति में होने के बावजूद, प्र.मंत्री मोदी ने पाकिस्तान के साथ ''सीज़फायर'' के लिए सहमति दी

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 जून। लंबे समय बाद, इंडिया गठबंधन की विपक्षी पार्टियाँ एकजुट हुईं और मोदी सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का सत्र बुलाने की मांग की।

विपक्ष का मानना है कि प्रधानमंत्री इस विचार के प्रति कतई इच्छुक नहीं हैं, बल्कि इसके विपरीत, उन्होंने मीडिया में ऐसी खबरें फैलाने की कोशिश की है जिससे कांग्रेस को डराया जा सके कि सरकार 25 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहती है।

विपक्षी दलों का यह भी मत है कि सरकार की मंशा ध्यान भटकाने की है ताकि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े मुद्दों से बचा जा सके, जबकि विपक्ष सरकार से कई गंभीर सवाल पूछना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी तक भी

- कांग्रेस को इस बात की भी खुशी है कि अन्ततोगत्वा, मृत-प्रायः इण्डिया गठबंधन फिर संगठित सा हुआ है, मोदी सरकार के समक्ष, संसद का सत्र बुलाने की मांग पर।
- विपक्ष के संगठित होने का एक कारण यह भी है कि विपक्ष को इस बात से काफी निराशा हुई कि ''ऑपरेशन सिंदूर'' व उसके बाद भी उसने मोदी सरकार को पूर्ण समर्थन दिया था, पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए, पर, प्र.मंत्री मोदी ''ऑपरेशन सिंदूर'' का उपयोग कर रहे हैं, राजनीति लाभ के लिए, वोट व चुनाव में।
- अतः अब राहुल भी पूर्णतया आक्रामक हो रहे हैं, प्र.मंत्री के खिलाफ।

विपक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं।

हालाँकि विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद और पाकिस्तान के साथ सीमित सैन्य टकराव के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में सरकार का पूरा समर्थन किया था, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यवाही का राजनीतिक लाभ उठाकर चुनावों में वोट की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मोदी की मंशा और इरादों को लेकर विपक्ष काफी असहज महसूस कर रहा है।

मुख्य सवाल यह है कि जब भारत रणनीतिक रूप से पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा था तो युद्धिवराम क्यों किया गया? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के दबाव में आकर पाकिस्तान पर हमले रोकने का आदेश दिया?

आज भोपाल में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री से कहा, ''नरेन्द्र सरेंडर'' और प्रधानमंत्री ने वास्तव में वही किया।

सूत्रों ने कहा, अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप बार-बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ही युद्धिवराम करवाया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर अब तक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जासूसी का आरोपी शकूर खान 7 दिन के पुलिस रिमांड पर

जयपुर, 3 जून। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर प्रथम ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में सरकारी कर्मचारी शकूर खान को दस जून तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। बताया जा रहा है कि शकूर खान पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सालेह मोहम्मद के निजी सहायक के तौर पर भी काम कर चुका है।

जांच एजेंसी ने मंगलवार को आरोपी को अदालत में पेश किया। जांच एजेंसी की ओर से अदालत से आरोपी को दस दिन के लिए पुलिस अभिरक्षा में सौंपने की गुहार की। एजेंसी की ओर से कहा गया कि आरोपी ने अब तक की

- बताया जाता है कि पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद का निजी सहायक शकूर खान पाक दूतावास के कई लोगों के सम्पर्क में हैं।

पूछताछ में कई जानकारियां दी हैं। उससे पूछताछ करनी है कि वह किन-किन लोगों के संपर्क में था। वहीं देश में उसका कौन सहयोग कर रहा था। इसके लिए उसे दस दिन के रिमांड पर दिया जाए। इस पर अदालत ने आरोपी को सात दिन के रिमांड पर दस जून तक जांच एजेंसी को सौंपा है।

पूछताछ में सामने आया है कि वह भारत में पाकिस्तान के हाई कमीशन के अफसर रहे एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में था और वह पाकिस्तान एंबेसी में सोहेल कमर से भी मिलता था। आरोपी शकूर खान भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर मंगलियों की ढाणी,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका को नहीं भा रहा, भारत का रूस से हथियार खरीदना

अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ''हॉवर्ड लटनिक'' ने यह बात अमेरिका-भारत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की लीडरशिप समिट को संबोधित करे हुए उजागर की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 जून। भारत के रूस से सैन्य उपकरण खरीदने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए ब्रिक्स के साथ भारत की साझेदारी ने अमेरिका को ''गलत ढंग से प्रभावित किया'', अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने यह बात स्वीकार की है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत ने इन मुद्दों को संबोधित किया है और अब दोनों देश ''ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद है'', और एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता ''बहुत दूर नहीं'' है।

लटनिक ने सोमवार को वॉशिंगटन डीसी में आयोजित यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) लीडरशिप समिट के आठवें संस्करण में अपने मुख्य भाषण के दौरान कहा, जब दोनों पक्षों ने सही लोगों को बातचीत की मेज पर बिठाया, तो हमने सब ठीक कर लिया।''

- इसके अलावा अमेरिका, भारत के ब्रिक्स संगठन में सक्रिय होने से भी खुश नहीं है।
- अमेरिका का मानना है कि ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के संगठन) का मुख्य मकसद, अमेरिका की मुद्रा, डॉलर के आधिपत्य को कमज़ोर करना है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैकल्पिक मुद्रा का सृजन करना है।
- ये दोनों कृत्य, रूस से हथियार खरीदना व ब्रिक्स की सक्रिय सदस्यता धारण करना, भारत के प्रति अमेरिका के मन में कुछ खटास तो लाते ही हैं।

बातचीत के लिए सही व्यक्ति को लाने के महत्व पर जोर देते हुए लटनिक ने कहा कि अगर वे किसी आम ट्रेड मिनिस्टर को वार्ता के लिए लाते तो वार्ता अंतहीन होती कोई नतीजा नहीं निकलता।

हालाँकि, लटनिक ने यह भी स्वीकार किया कि भारत द्वारा किए गए कुछ कार्य, जैसे रूस से सैन्य उपकरण खरीदना, अमेरिका को पसंद नहीं आए। उन्होंने कहा, ''भारत सरकार अब इन मुद्दों को विशेष रूप से और सीधे तौर पर संबोधित कर रही है।''

लटनिक ने कहा, ''भारतीय अर्थव्यवस्था असाधारण है, आपकी मानव संसाधन क्षमता अद्भुत है, आपकी विकास दर शानदार है। लेकिन फिर भी, कुछ चीजें जो भारत सरकार ने कीं, उन्होंने अमेरिका को गलत रूप में प्रभावित किया।''

उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, ''जैसे कि आप सामान्यतः रूस से अपने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दस जून को हो सकता है, महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों धड़ों का विलय

दस जून एनसीपी का स्थापना दिवस है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 जून। जैसे-जैसे एनसीपी का स्थापना दिवस, 10 जून नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे अजित पवार और उनके चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की वार्ता तेज होती जा रही है। अगर यह प्रगति साकार हो जाती है तो यह केवल महाराष्ट्र के लिये ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति के लिये भी एक बड़ी घटना होगी, क्योंकि मराठा दिग्गज शरद पवार विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के घेरे से बाहर हो जायेंगे तथा केन्द्र में मोदी सरकार को समर्थन दे रहे एनडीए के लोकसभा सांसदों की संख्या 300 के आँकड़े को पार कर जायेगी, जो इस समय 293 है।

महाराष्ट्र की राजनीति के शीर्षस्थ सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि इस विलय को औपचारिक रुप देने के लिये अगले दो दिन में शरद पवार और उनके भतीजे के बीच रुबरु बातचीत होने की संभावना है। शरद पवार के नजदीकी

- एनसीपी के दोनों धड़ों का विलय महाराष्ट्र के राजनैतिक समीकरणों में भारी उलटफेर कर सकता है, साथ ही केन्द्र में भी इसका असर दिख सकता है।
- विलय के साथ ही शरद पवार विपक्ष के गठबंधन, इंडिया से बाहर हो जाएंगे और एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। लोकसभा में शरद पवार के 8 सांसद हैं और इस विलय से एनडीए के सांसदों की संख्या 300 के पार हो जाएगी।
- शरद पवार गुट के दूसरी श्रेणी के नेता इस विलय के ज्यादा इच्छुक हैं, क्योंकि उनके व्यवसायिक हित व राजनैतिक अस्तित्व दांव पर लगे हैं।
- विशेषज्ञों का कहना है कि शरद पवार का एकमात्र फोकस अपनी बेटी सुप्रिया सुले का भविष्य सुरक्षित करने पर है, क्योंकि खुद तो अपने राजनैतिक जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं।

सूत्रों ने जानकारी दी कि उनके ऊपर उनकी पार्टी की दूसरी कतार के नेताओं का जबरदस्त दबाव है, क्योंकि वे अपना राजनैतिक भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने, पार्टी प्रमुख होने के बावजूद, अपने हाथ खड़े कर दिये है तथा इस मामले में निर्णय उन पर छोड़ दिया है।

लेकिन अजित गुट चाहता है कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी 6 जून को कटरा -श्रीनगर रेल लिंक का उद्घाटन करेंगे

जम्मू, 03 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी छह जून को बहुप्रतीक्षित कटरा-श्रीनगर रेल लिंक का उद्घाटन करेंगे।

इससे पहले गत 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस रेल लिंक का उद्घाटन कार्यक्रम खराब मौसम के

- पहले यह उद्घाटन 19 अप्रैल को होना था पर खराब मौसम के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। बाद में 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के कारण और विलम्ब हो गया।

पूर्वानुमान के कारण स्थगित कर दिया गया था।

गत 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमले और इसके बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात प्रधानमंत्री का केन्द्रशासित प्रदेश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'एशिया के देश अपनी जीडीपी का 5 प्रतिशत सेना की तैयारी पर खर्च करें'

अमेरिका के रक्षा मंत्री के आह्वान को ज्यादा स्वीकार नहीं किया गया, सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला डायलॉग में

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 जून। सिंगापुर में आयोजित एशिया के प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन ''शांग्री-ला डायलॉग'' में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हैगसथ ने स्पष्ट संदेश दिया: अमेरिका इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को नहीं छोड़ रहा है। लेकिन अमेरिका द्वारा दिए जा रहे सैन्य आश्वासन के बावजूद एशिया के कई नेताओं के लिए राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी व्यापार नीतियों के कारण उत्पन्न आर्थिक अनिश्चितता चिंता का विषय बनी हुई है।

हैगसथ का भाषण आंशिक रूप से आश्वासन देने वाला था और आंशिक रूप से उकसाने वाला। उन्होंने एशियाई देशों से यूरोपीय सहयोगियों की तरह रक्षा बजट को जीडीपी का 5 प्रतिशत तक बढ़ाने का आग्रह किया। यह एक ऐसा आंकडा है, जिसने उन विकासशील देशों को चकित कर दिया है, जो अब

- अधिकतर ने इस दलील को अमेरिका की अपने हथियार बेचने की योजना का अंश माना।
- विशेषकर, मलेशिया के प्रधानमंत्री व उनके प्रमुख सलाहकार का मत था कि अमेरिका एशियाई देशों की मजबूरियों से वाकिफ नहीं है। एशिया में अभी कई देशों की प्राथमिकता है, अपने देशवासियों को गरीबी की सीमा से ऊपर लाना। इस स्थिति में इन देशों को यह सलाह देना है कि वे अपने डिफैंस बजट में वृद्धि करे, बेवकूफी की बात लगती है।
- इन नेताओं के अनुसार, सही सलाह अमेरिका के लिए है कि वे उनके राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फैलायी गई अनिश्चितता को खत्म करें। जिससे व्यापार बढ़े और युद्ध की संभावना ही खत्म हो।

भी अपनी आबादी को गरीबी से बाहर निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ कुछ को अधिक मजबूत सैन्य सहयोग की अपील सार्थक लगी, वहीं, कई अन्य इसे एक लेन-देन आधारित दृष्टिकोण के रूप में देख रहे थे, जिसमें हथियारों की बिक्री के बदले व्यापार में नरमी की अपेक्षा की जाती है।

यह भाषण ऐसे समय में आया, जब ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीतियों को लेकर चिंता बढ़ रही है। एक हफ्ते पहले आसियान (ए.एस.ई.ए.एन.) नेताओं की बैठक में ट्रंप के टैरिफ मुख्य विषय थे। वियतनाम और कंबोडिया जैसे देश अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिससे वे चीन के साथ आर्थिक संबंध गहरे करने पर विचार कर रहे हैं, भले ही वे क्षेत्र में बीजिंग की आक्रामकता को लेकर सतर्क हों।

जब शांग्री-ला सम्मेलन में हैगसथ से इन आर्थिक तनावों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने टालमटोल की। उन्होंने मजाक में कहा, ''टैरिफ नहीं, टैंक,'' यह दर्शाते हुए कि आर्थिक मुद्दे उनकी जिम्मेदारी नहीं हैं। इसके बजाय उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका क्षेत्र के लिए रणनीतिक रूप से प्रतिबद्ध है और कहा कि अमेरिका ''उन मामलों में सहयोग चाहता है जहाँ शांति और समृद्धि के लिए हमारे साझा हित मेल खाते हैं,'' साथ ही यह भी चेतावनी दी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मतदान के आंकड़े अपडेट करने की नई व्यवस्था लागू होगी

नयी दिल्ली, 03 जून। चुनाव आयोग मतदान के आंकड़े अपडेट करने की एक नयी व्यवस्था करने जा रहा है जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी (पीआरओ) को मतदान बंद होने के बाद तुरंत, मतदान केंद्र छोड़ने से पहले मतदान के आंकड़े आयोग के एकीकृत डिजिटल ऐप

- चुनाव आयोग ने कहा मतदान खत्म होते ही मतदान केन्द्र से ही डेटा अपडेट करना होगा। यह व्यवस्था बिहार चुनाव से लागू होगी।

'ईसीआईएनईटी' में दर्ज करना होगा, ताकि क्षेत्र-वार मतदान प्रतिशत की सूचना देने में विलम्ब कम से कम हो। यह व्यवस्था बिहार विधान सभा चुनाव के साथ शुरू की जायेगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेद्र कुमार के नेतृत्व में आयोग द्वारा चुनाव

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आम अमेरिकी के साधारण उपयोग का 90 प्रतिशत सामान चीन सप्लाई करता है

अमेरिका चाहता है, यह सामान भारत सप्लाई करे जिससे अमेरिका की चीन पर निर्भरता कम हो

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 जून। भारत द्वारा रूस से हथियारों और सैन्य साज़ो-सामान की खरीद अमेरिका को चुभती है। यह भारत-अमेरिका संबंधों में एक बाधा है, यह बात अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने खुद कही है।

हालांकि उन्होंने भारत को एक महान देश बताया गया, जिसमें विविध क्षमताएँ हैं, विशेष रूप से प्रतिभाशाली हैं, लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में बड़ी सफलताएँ हासिल कर सकते हैं। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय टेलीविज़न नेटवर्क से बातचीत में अमेरिकी वाणिज्य सचिव लटनिक ने ये विचार व्यक्त किए।

लटनिक ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की पहली प्राथमिकता ''अमेरिका फर्स्ट'' नीति के तहत उन्नत निर्माण को बढ़ावा देना है। लेकिन इसके अलावा, अमेरिका के पास मित्र देशों और सहयोगियों के साथ सहयोग के कई क्षेत्र खुले हैं, जिनमें भारत भी संभावनाएं तलाश सकता है। उन्होंने बताया कि अमेरिका कुछ अत्याधुनिक क्षेत्रों में नीति के तहत उच्च तकनीक वाले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा है।

इन खास क्षेत्रों के बाहर, निर्माण का एक बड़ा क्षेत्र है, जहां भारत अवसरों का लाभ उठा सकता है और इन उत्पादों के साथ अमेरिकी बाजार तक पहुंच बना सकता है। औद्योगिक सहयोग के इन क्षेत्रों में दोनों देशों के लिए फायदे की बड़ी संभावनाएं हैं।

- अमेरिका की दृष्टि से दूसरा क्षेत्र जिसमें भारत- अमेरिका सहयोग, अच्छी तरह बढ़ सकता है, वह है ए.आई. आधारित एडवांस सिस्टम। अमेरिका यह स्वीकार करता है, कि भारत-अमेरिका के इस क्षेत्र में सहयोग से दोनों देशों को लाभ ही लाभ है।
- दोनों देशों का मानना है, अगर आपसी सहयोग से काम हो तो, भारत-अमेरिका व्यवसाय थोड़े से समय में ही 500 बिलियन डॉलर की सीमा पार कर लेगा।

वाणिज्य सचिव लटनिक के वक्तव्य के पीछे एक ठोस तर्क और सोच है। वर्तमान में अमेरिका में आम नागरिकों की रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा चीन से आता है। इसका परिणाम यह है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में अत्यधिक झुका हुआ है।

राष्ट्रपति ट्रंप की नीति के तहत, अमेरिका इस असंतुलन को सुधारना चाहता है और इसके लिए वैकल्पिक आपूर्ति शृंखलाएं विकसित करना चाहता है। यह अमेरिका की रणनीति का हिस्सा है और अमेरिका इस दिशा में भारत को एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में देखना पसंद करेगा।

दूसरी ओर, एक हल्के-फुल्के अंदाज़ में वाणिज्य सचिव ने यह भी कहा कि रूस से भारत द्वारा हथियारों की पूरी श्रृंखला की खरीद, विशेषकर यूक्रेन संकट के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, अमेरिकी नीति निर्माताओं में भारत के प्रति नकारात्मक भावनाएँ पैदा कर सकती हैं।

अमेरिका को विशेष रूप से यह बात खल रही है कि भारत द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (एसएएम 400) की खरीद हालिया पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाक संघर्ष के दौरान बेहद प्रभावशाली साबित हुई तथा भारत अब इस प्रणाली का एक और सेट तैनात करने की योजना बना रहा है।

हाल ही में हुए आतंकी हमले से पहले भारत धीरे-धीरे अपने रक्षा उपकरणों की खरीद में विविधता लाया था, जिसमें अमेरिकी सैन्य उपकरण भी शामिल थे। लटनिक ने यह नोट किया कि हाल के दिनों में भारत ने अमेरिकी रक्षा प्रणालियों और हथियारों की खरीद की शुरुआत की है।

भारत और अमेरिका के बीच सहयोग का एक अन्य क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है। उन्नत एआई प्रणालियों को भारतीय और अमेरिकी विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा सकता है, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा। लटनिक ने माना कि भारत की इस क्षेत्र में दक्षता को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रामदरबार का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुरु

अयोध्या, 03 जून। श्रीराम जन्मभूमि पर राम दरबार समेत आठ मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ प्रायश्चित कर्म और कलश के साथ शुरू हो गया। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में मंगलवार को वैदिक मंत्रोच्चारण संग विधि-विधान पूर्वक पंचांग पूजन, मंडप

- गंगा दशमी के दिन सुबह 11.25 से 11.40 के मुहुर्त में रामदरबार की मूर्तियां प्रतिष्ठापित होंगी।

प्रवेश, यज्ञ मंडप पूजन, ग्राह योग, अग्नि स्थापन, वन कर्मकुटी और जलाधिवास का अनुष्ठान किया गया। बुधवार चार जून को देवताओं का पूजन, अन्नाधिवास, हवन, देवस्नान, प्रसाद स्नान, शिखर स्नान, नगर भ्रमण शैय्याधिवास, न्यास का कार्यक्रम होगा।

प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान काशी के विद्वान पंडित जयप्रकाश के नेतृत्व में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)